1	2	3	4	5
Harduaganj B&C	Aligarh	425	(2x40—4x60—1x105)	714
Paricha . . .	Jhansi	220	(2x110)	573
Anpara . .	Sonbhadra	630	(3x210)	3979
Tanda	Faizabad	330	(3x110)	460
RPH Kanpur . .		65	(Small units)	..
Others (UPSEB) . .		33.5	(,,)	5
TOTAL THERMAL . .	(UPSEB)	3549.5		12635
NTPC				
Singrauli . . .	Sonbhadra	2050	(5x210+2x500)	14053
Rihand	,,	1000	(2x500)	6511
Auraiya (GT) . . .	Itawah	652	(4x112+2x102)	3818
Unchahar . . .	Rai Bareli	420	(2x210)	203
Dadri (NCTPP) . .	Ghaziabad	210	(1x210)	New Unit
Dadri (GT) . . .	,,	262	(2x131)	32
TOTAL NTPC . .	THERMAL	4594		24619

छोटी पन बिजली परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये कार्यवाही योजना

4325. **श्री वीरेन्द्र जे० शाह :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार देश में हिमालय पर्वत से लगे राज्यों में छोटी-छोटी पने बिजली परियोजनाओं का निर्माण करके विद्युत उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यवाही योजना तैयार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इससे स्थापित की जाने वाली अतिरिक्त विद्युत उत्पादनों क्षमता का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार के पास उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए निजी क्षेत्र को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने संबंध में भी कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार और कितनी कितनी सहायता दिए जाने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) समग्र देश के नहर प्रपात, सिंचाई बांधों, रन आफ दी रोवर तथा प्राकृतिक प्रपातों के विद्यमान जलीय ससाधनों से मिनी माइक्रो जल विद्युत (3 मे0वा0 तक) की शक्यता अभिज्ञात किए जाने को प्रोत्साहन दिये जाने से सबधित सरकार का एक कार्यक्रम हैं। ग्रिड से संबद्ध मिनीमाइक्रो जल विद्युत परियोजनाओं के लिए वैद्युत एवं मकेनिकल उपस्कर और सिविल कार्यों हेतु स्वीकार्य पूंजीगत लागत की राशि के 25% तक की राशि केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किए जाने की सुविधा दी जा रही है। ग्रिड से सम्बद्ध विकेन्द्रित परियोजनाएं जो कि मुख्यत: दूर-दराज एव पर्वतीय क्षेत्रों में

अधिष्ठापित की जाती है, मिनो/माइक्रो जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी किए जाने के लिए इस प्रकार की परियोजनाओं की लागत को 50 % तक की राशि आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाती है । यह आशा की जाती है कि समग्र देश में आठवीं योजना के दौरान मिनी/माइक्रो जल विद्युत परियोजनाओं का विकास करके 1000 मेघावाट की अतिरिक्त क्षमता जोड़ी जा सकेगी । ऐसी परियोजनाओं के संबंध में राज्यवार लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि इस प्रकार के क्रियाकलाप विभिन्न राज्यों में उपलब्ध क्षमता पर निर्भर करते है । इस समय देश में हिमालय के निकटवर्ती राज्यों में लघु जल विद्युत परियोजनायें (3 मे०वा० से 15 म०वा० तक की क्षमता वाली) निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं । इन परियोजनाओं में जोड़े जाने वाली अतिरिक्त संभावित विद्युत उत्पादन क्षमता 97.25 मे.वा. होगी । इन परियोजनाओं का राज्यवार का ब्यौरा विवरण में दिया गया है । **(नीचे देखिए)**

(ग) और (घ) इस प्रकार की मिनो/माइक्रो जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जो आर्थिक सहायता की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है इस प्रकार की सुविधा निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई जाएगी बशर्ते इस प्रकार की मिनो/माइक्रो परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत को मुख्यतः सार्वजनिक वितरण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा ।

विवरण

हिमाचल पर्वत के निकटवर्ती राज्यों में निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजनाएं (3 मेघावाट से 15 मेघावाट तक की क्षमता वाली)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	राज्य	अधिष्ठापित क्षमता (मेघावाट)
1.	चिरोट	हिमाचल प्रदेश	4.5
2.	बनर	हिमाचल प्रदेश	12
3.	गज	हिमाचल प्रदेश	10.5
4.	कारगिल	जम्मू व कश्मीर	3.75
5.	चेनानी 2 तथा 3	जम्मू व कश्मीर	6
6.	अटवाटू	जम्मू व कश्मीर	7.5
7.	सेवा–3	जम्मू व कश्मीर	6
8.	सोबला	उत्तर प्रदेश	6
9.	म्योंगचू	सिक्किम	4
10.	उत्तरी रोंगनीचू	सिक्किम	8
11.	तूरानॉग	अरुणाचल प्रदेश	6
12.	लघु जल विद्युत	अरुणाचल प्रदेश	6
13.	डलाईमा	असम	6
14.	सेरलुई-ब	मिजोरम	9
		जोड :	97.25

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दामोदर घाटी निगम द्वारा मैथन परियोजना का निर्माण

4326. **श्री वीरेन जे. शाह :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दामोदर घाटी निगम द्वारा सोवियत संघ के सहयोग से मैथन राइट बैंक परियोजना का निर्माण करने के संबंध में निर्णय किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भूतपूर्व सोवियत संघ के विराव के कारण परियोजना का कार्य अनिश्चितता की स्थिति में है ;